

भारत के विकास और वैश्विक चुनौतियों से निपटने में भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका*

श्री संजय मल्होत्रा

सुप्रभात।

मुझे आपके साथ अपने विचार साझा करने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात रखता हूँ। आप जैसे प्रतिभाशाली लोगों के बीच यहां उपस्थित होना वास्तव में खुशी की बात है।

मुझे 2008-09 में यहां बिताए गए 11 महीने याद हैं: एंटी-ट्रस्ट इकोनॉमिक्स पर बॉब विलिंग के पाठ्यक्रमों के साथ अर्थशास्त्र की मूल बातें (भगवान उनकी आत्मा को आशीर्वाद दें), एंगस डीटन, एलन ब्लाइंडर (जिन्होंने सोचा था कि मौद्रिक नीति और संचार पर उनकी सीख आगे चलकर बहुत काम आएंगे!) और ग्रॉसमैन, छोटे और एकजुट एमपीपी बैच के जीवंत सौहार्द तक, पतझड़ और वसंत में खूबसूरत ग्रामीण इलाकों में परिवार की सैर, और प्रिंसटन-हार्वर्ड फुटबॉल प्रतिद्वंद्विता, सभी स्मृति में स्पष्ट रूप से अंकित हैं।

पिछले एक दशक में भारत की कितनी बड़ी विकास गाथा रही है, उससे आप सभी परिचित हैं। हम औसतन 6.1% प्रति वर्ष की दर से बढ़े हैं,¹ जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में 3.2% की वृद्धि हुई है और चीन जैसे हमारे निकटतम समकक्षों में 5.6% और इंडोनेशिया में 4.2% की वृद्धि हुई है।² मैं विकास के मुख्य चालकों - उपभोग, निवेश, सेवाओं आदि पर चर्चा नहीं करूंगा। मैं उन सक्षमकर्ताओं के बारे में बात करूंगा जो पृष्ठभूमि में काम करते हैं जो मुख्य कारकों के लिए एक सुविधाजनक वातावरण बनाते हैं।

मैं इस सुविधाजनक पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदान करने में आरबीआई की भूमिका के बारे में बात करूंगा। मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगा कि कई केंद्रीय बैंकों के विपरीत, आरबीआई, एक पूर्ण-विकसित, पूर्ण-सेवा प्रदाता केंद्रीय बैंक है, जिसके पास

* 18 अप्रैल, 2026 को प्रिंसटन विश्वविद्यालय, यूएसए में भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा का संबोधन।

¹ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के आंकड़ों के आधार पर 2015-16 से 2024-25 की अवधि से संबंधित है।

² आईएमएफ डेटा के आधार पर 2016-2025 की अवधि से संबंधित है।

मौद्रिक नीति, मुद्रा प्रबंधन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन और बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और भुगतान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण से लेकर विविध जिम्मेदारियां हैं। बैंको के बैंक होने के अलावा, यह केंद्र और राज्य सरकारों का बैंक एवं ऋण प्रबंधक है। इसके अलावा, आरबीआई की भी विकासात्मक भूमिका है। हालांकि, मैं रिज़र्व बैंक के मुख्य कार्यों पर संक्षेप में बात करूंगा, जो परिवारों, व्यवसायों और सरकारों के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करते हैं।

I. मूल्य स्थिरता

पहला मूल्य स्थिरता है। यह एक ऐसा लक्ष्य है जिसका पालन सभी केंद्रीय बैंक करते हैं – ऐसा न केवल इसलिए कि मुद्रास्फीति एक प्रतिगामी कर है, जो सबसे गरीब को सबसे अधिक हानि पहुंचाता है, बल्कि इसलिए भी कि व्यवसायों और परिवारों के लिए आत्मविश्वास से योजना बनाने और निवेश करने के लिए मूल्य स्थिरता महत्वपूर्ण है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देशों के विपरीत, जिनके पास स्पष्ट दोहरा अधिदेश है और न्यूजीलैंड जैसे अन्य देश, जिनके पास स्पष्ट रूप से एकल अधिदेश है, हमारे पास विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक अधिदेश के रूप में मूल्य स्थिरता है।

हमने 2016 में औपचारिक रूप से इस अधिदेश को अपनाया। हमारे पास एक फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग (एफआईटी) फ्रेमवर्क है। यह लचीला है क्योंकि, जबकि हमारे पास एक पॉइंट टारगेट (4%) है, जिसमें दोनों तरफ 2% का एक बैंड है। आंतरिक और साथ ही बाहरी, सीपीआई बास्केट में भोजन और ईंधन (आपूर्ति पक्ष कारक) के बड़ी भारिता को देखते हुए, लक्ष्य के चारों ओर अपेक्षाकृत व्यापक आघात सहनीयता बैंड हमें आपूर्ति के आघातों को नेविगेट करने देता है।

हम मौद्रिक नीति का संचालन कैसे करते हैं, विशेष रूप से इस तरह की उच्च अनिश्चितता पैदा करने वाली वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में? मुझे याद आ रहा है कि एलन ग्रीनस्पैन ने एक बार कहा था कि अनिश्चितता केवल मौद्रिक नीति परिदृश्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है; अपितु यह एक पारिभाषिक विशेषता है। दूसरे शब्दों में, केंद्रीय बैंकिंग में, आपके पास जो एकमात्र निश्चितता वह अनिश्चितता है।

ऐसा इसलिए है क्योंकि कम अनिश्चितता और अस्थिरता के समय में भी, अर्थव्यवस्था और मौद्रिक नीति संचरण जटिल

और निरंतर परिवर्तनशील रहते हैं। वर्षों से अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न व्यापक आर्थिक चर और निर्मित मॉडल के बीच संबंधों को समझने की कोशिश की है। हालांकि, हर मॉडल, चाहे वह कितना भी विस्तृत हो या वैचारिक और अनुभवजन्य रूप से कितनी भी अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया हो, वह हमारे द्वारा दैनिक आधार पर अनुभव किए गए सभी पेचीदगियों के साथ दुनिया का एक बेहद सरलीकृत प्रतिनिधित्व है। उदाहरण के लिए, फिलिप्स वक्र का स्लोप या ब्याज की प्राकृतिक दर अनिश्चित है। यह अपने आप में नीति निर्माण में अनिश्चितता का परिचय देता है। डेटा को लेकर भी अनिश्चितता है। अनिश्चितता के साथ-साथ, जहां हम किसी परिणाम की संभावना की भविष्यवाणी करने में असमर्थ हैं, हमारे पास अब अप्रत्याशितता भी है, जहां परिणामों की भविष्यवाणी भी नहीं की जा सकती है। इससे मौद्रिक नीति बनाना और भी कठिन हो जाता है।

चूंकि, अनिश्चितता मौद्रिक नीति के लिए प्रमुख मद है, इसलिए हमारे नीति-निर्माण के व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं बदलते हैं। यह केवल उनका प्रयोग है, जो बदलता है।

पहला सिद्धांत **इष्टतमता की तुलना में सुदृढ़ता को प्राथमिकता देना है**। इसमें जोखिम प्रबंधन शामिल है। हम अनिश्चितताओं से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को समझने की कोशिश करते हैं, उनकी संभावनाओं का आकलन करते हैं, उनके प्रभाव को मापते हैं और फिर एक ऐसी नीति तैयार करते हैं जो मूल्य स्थिरता और विकास के सर्वोत्तम नीतिगत परिणामों को बेहतर बनाती है।

इसके अतिरिक्त ध्यान में रखा जाने वाला एक अन्य सिद्धांत है **ब्रेनार्ड का क्षीणन का सिद्धांत**। यदि केंद्रीय बैंक अपने साधनों में परिवर्तन के प्रभाव के परिमाण के बारे में अनिश्चित है, तो उसे निश्चित परिणाम की तुलना में उस साधन को कम बदलना चाहेगा। दूसरे शब्दों में, यह क्रमिकता की नीति है। हालांकि, इस नियम के अपवाद हैं जैसा कि मुद्रास्फीति की दृढ़ता के मामले में होता है।

ब्रेनार्ड के सिद्धांत का एक परिणाम है। यदि ब्रेनार्ड सिद्धांत के अनुसार केंद्रीय बैंक अनिश्चितता के दौरान प्रतिक्रिया नहीं करते हैं या धीरे-धीरे प्रतिक्रिया करते हैं, तो मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं को प्रबंधित करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए, **मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं को स्थिर करना** आवश्यक हो जाता है, जो एक

और महत्वपूर्ण उद्देश्य है जिसे हम भविष्य के लिए गाइडेंस प्रदान करने सहित विभिन्न साधनों के माध्यम से प्राप्त करते हैं।

हमारा चौथा मार्गदर्शी सिद्धांत **पारदर्शिता** है, जो पूर्वानुमेयता और विश्वसनीयता प्रदान करता है, और इस तरह प्रभावशीलता को बढ़ाता है। यह आर्थिक एजेंटों के मन से अनिश्चितता को भी दूर करता है।

अंत में, केंद्रीय बैंक की रणनीति और नीतिगत निर्णयों का **स्पष्ट संचार**, मौद्रिक नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली आधार है। यह दृष्टिकोण की स्पष्टता लाता है और इस प्रकार पारदर्शिता को बेहतर बनाने और मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं को स्थिर करने में मदद करता है।

वर्तमान संकट की बात करें तो यह हमें विशेष रूप से प्रभावित करता है क्योंकि पश्चिम एशिया हमारे निर्यात का लगभग छठा हिस्सा, हमारे आयात का पांचवां हिस्सा, कच्चे तेल के आयात का आधा, हमारे उर्वरकों के आयात का दो-पांचवां हिस्सा और हमारे आवक विप्रेषण का लगभग दो-पांचवां हिस्सा देता है। इस तरह की आपूर्ति के आघातों के लिए उचित मौद्रिक नीति प्रतिक्रिया पहले दौर के प्रभाव को इस हद तक देखना है कि यह दूसरे दौर की गतिशीलता को प्रभावित नहीं करता हो। दूसरे दौर के प्रभाव वास्तविक चिंता का विषय हैं। यदि आपूर्ति शृंखला में व्यवधान लंबे समय तक जारी रहता है तो वे अमल में लाए जा सकते हैं। फिर, आपूर्ति के आघातों के रूप में जो शुरू हुआ वह सामान्य मूल्य स्तर में अंतर्निहित हो सकता है। ऐसे में मौद्रिक नीति की प्राथमिक भूमिका कुंद मांग संपीड़न के बजाय मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं पर इसके प्रभाव के माध्यम से इस अवरोध को रोकना है।

इसके अलावा, इस तरह के अनिश्चित समय में, **चुस्त और फुर्तीला होना, व्यापक नीतिगत रुख बनाए रखना** और नीति के भविष्य के मार्ग की दृढ़ प्रतिबद्धताएं बनाने से बचना महत्वपूर्ण है। ऐसी परिस्थितियों में, हमारा व्यापक दृष्टिकोण और भी अधिक डेटा पर निर्भर होना और जोखिमों के संतुलन का लगातार पुनर्मूल्यांकन करना रहा है। इसलिए हम अब वेट एंड वॉच मोड में हैं। इसके अलावा, हम पिछले कुछ नीतिगत समीक्षाओं से तटस्थ रुख बनाए हुए हैं। यह मुद्रास्फीति-वृद्धि की गतिशीलता के विकसित होने पर प्रतिक्रिया करने के लिए लचीलेपन को संरक्षित करता है।

महामारी से लेकर यूक्रेन युद्ध तक लगातार आघातों से निपटने में एफआईटी के साथ हमारा एक दशक का अनुभव बताता है कि इसने हमारी अच्छी सेवा की है।

जब से हमने एफआईटी को अपनाया है, हमारी औसत हेडलाइन मुद्रास्फीति 4.7% (सितंबर 2016 से दिसंबर 2025) तक गिर गई है, जो पिछले वर्षों (अप्रैल 2012 से अगस्त 2016) में 7.4% से कम है।

इसके अलावा, हेडलाइन मुद्रास्फीति की अस्थिरता उसी अवधि में 2.4% से 1.7% तक कम हो गई।

मुद्रास्फीति की प्रत्याशाएँ बेहतर रूप से सुदृढ़ और कम अस्थिर हैं।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में भी, एफआईटी ढांचा सफल रहा है। 2006-2015 के दौरान आई और ईएमडीई दोनों के बीच उच्चतम औसत मुद्रास्फीति से, भारत में मुद्रास्फीति पिछले दशक के दौरान ईएमडीई के औसत से नीचे आ गई है।

यह उल्लेख करना भी उचित है कि कोविड और यूक्रेन युद्ध के कारण आपूर्ति शृंखला में व्यवधान के बाद, भारत में मुद्रास्फीति कई उन्नत देशों की तुलना में तेजी से लक्षित हो गई।

मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने में राजकोषीय-मौद्रिक समन्वय की भूमिका

यद्यपि हम मूल्य स्थिरता में सुधार के लिए मौद्रिक नीति और लोचनीय मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को श्रेय देते हैं, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि इस संबंध में राजकोषीय नीति की समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका है। यह विशेष रूप से हमारे जैसे देश में है, जहां आपूर्ति पक्ष के कारक मुद्रास्फीति में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं।

सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कीमतों के दबाव को रोकने के लिए आपूर्ति पक्ष के उपायों के साथ मौद्रिक नीति कार्रवाइयों को जोड़ा है। पहला, सरकार ने कृषि में सुदृढ़ता स्थापित करने और बरसाती तथा फसल रोगों की अनिश्चितताओं से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को कम करने को प्राथमिकता दी है। यह सिंचाई के तहत अधिक भूमि, बेहतर बीज; फसल प्रबंधन और कटाई के बाद की प्रथाओं को शामिल करके प्राप्त किया गया है। दूसरा, सरकार ने कीमतों के दबाव के समय में उपयोग की जाने

वाली आवश्यक वस्तुओं के लिए खुदरा वितरण नेटवर्क बनाने के अलावा, भंडारण और आपूर्ति शृंखला के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है। तीसरा, इसने ईंधन की कीमतों की अस्थिरता को कम करने के लिए तेल पर उत्पाद शुल्क का उपयोग एक साधन के रूप में किया है।

मौजूदा संकट के दौरान तेल और गैस का घरेलू उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। आयात के स्रोतों में विविधता लाई जा रही है। हालांकि तेल की कोई कमी नहीं है, हमारे द्वारा बनाए गए भंडार को देखते हुए, औद्योगिक प्रयोजनों के लिए गैस की कुछ राशनिंग की गई है। तेल विपणन कंपनियों और सरकार ने उपभोक्ताओं पर गैस पर कुछ मूल्य दबावों को डालते हुए तेल में मूल्य दबावों को अवशोषित कर लिया है।

इसके अलावा, हाल के वर्षों में कर संग्रह में बढ़ी हुई दक्षता और व्यय की गुणवत्ता में सुधार के माध्यम से राजकोषीय समेकन में लगातार प्रगति हुई है।

राजस्व पक्ष पर, जीएसटी को अपनाने और डिजिटलीकरण, सरलीकरण, युक्तिकरण और कर मूल्यांकन तथा संग्रह में मानव इंटरफ़ेस को कम करने सहित आयकर में व्यापक सुधारों ने कर वृद्धि में सुधार करने में मदद की है।³ 2018-19 से 2025-26 तक जीएसटी के बाद आठ साल की अवधि में सकल जीएसटी वृद्धि (केंद्र और राज्य राजस्व) 1.23 है। कॉरपोरेट कर की दर कम होने और व्यक्तिगत आयकर में वृद्धि के बाद से कॉरपोरेट कर में वृद्धि आम तौर पर एक से अधिक रहा है और पिछले पांच वर्षों में व्यक्तिगत आयकर में वृद्धि औसतन 1.7 रहा है।

व्यय पक्ष पर भी, सरकारी खर्च को बेहतर लक्षित किया जाता है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, जिससे लगभग 50 बिलियन अमरीकी डालर (मार्च 2024 तक)⁴ की बचत होने का अनुमान है; सार्वजनिक वितरण योजना जैसे विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों का डिजिटलीकरण; और राज्य सरकारों को निधियों का समय पर प्रवाह व्यय दक्षता बढ़ाने के कुछ उदाहरण हैं। महामारी के प्रति इसका दृष्टिकोण एक उदाहरण

³ कर वृद्धि को सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिशत परिवर्तन के सापेक्ष कर राजस्व में % परिवर्तन के अनुपात के रूप में मापा जाता है।

⁴ <https://dbt.bharat.gov.in/static-page-content/spagecont?id=18>

⁵ आईएमएफ राजकोषीय मॉनिटर, अप्रैल 2026।

है। फ्रंट-लोडिंग प्रोत्साहन पैकेजों के बजाय, जैसा कि अधिकांश देशों ने किया था, भारत ने समाज के कमजोर वर्गों और छोटी फर्मों का समर्थन करने के लिए एक लोचनीय और चुस्त दृष्टिकोण अपनाया।

सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय 2021-22 में 13.6% से घटकर 2025-26 (आरई) में 10.8% हो गया। इसके विपरीत, पूंजीगत व्यय में भारी वृद्धि हुई है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय का हिस्सा 2019-20 में 1.7% से बढ़कर 2025-26 (आरई) में 3.1% हो गया है। राज्यों को सहायता में पूंजीगत अनुदान को शामिल करते हुए, यह बढ़कर 3.9% (आरई) हो गया है।

केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा और जीडीपी अनुपात 2020-21 में 9.2% से घटकर 2025-26 (आरई) में 4.4% हो गया है। भारत का सामान्य सरकारी ऋण जीडीपी अनुपात 81.1% (2024-25 में) उचित है, जर्मनी और रूस⁶ के अलावा दुनिया की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाएं (यूएसडी में नाममात्र जीडीपी के संदर्भ में) में भारत की तुलना में अधिक ऋण अनुपात है।

II. वित्तीय स्थिरता

अब मैं वित्तीय स्थिरता पर आता हूं। यह वह आधार है जिस पर अर्थव्यवस्था समृद्ध होती है और स्थायी रूप से बढ़ती है।

वित्तीय स्थिरता से जुड़ा हमारा निहितार्थ हमारे व्यापक नियामक ढांचे में विधिवत परिलक्षित होता है। हम दीर्घकालिक विकास के लिए कुछ अल्पकालिक लाभ का त्याग करने के लिए तैयार हैं। जबकि कुछ लोग इसे रूढ़िवाद के रूप में मानते हैं, हम मानते हैं कि यह विवेकपूर्ण है। यह विभिन्न संकटों के दौरान हमारी सुदृढ़ता से स्पष्ट होता है। मैं इसे कुछ उदाहरणों के साथ उजागर करूंगा।

जब 1997-98 में एशियाई वित्तीय संकट इस क्षेत्र में फैल गया, तो इसने उन मुद्राओं और अर्थव्यवस्थाओं को नीचे ला दिया, जिसे केवल महीनों पहले निर्यात के बढ़ावा देने वाले विकास के मॉडल के रूप में समझा जा रहा था। भारत ने तुलनात्मक स्थिरता की स्थिति से इसे देखा और इसके कारण आकस्मिक नहीं थे।

आरबीआई ने पूंजी खाते पर नियंत्रण बनाए रखा था, विशेष रूप से निवासियों के लिए। अल्पकालिक विदेशी ऋण को विदेशी मुद्रा भंडार से काफी नीचे के स्तर पर बनाए रखा गया था, जो आसानी से कवर कर सकता था। इसने उस तरह के अल्पकालिक विदेशी मुद्रा उधार की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसने हमारे क्षेत्रीय पड़ोसियों को अचानक इस भावना का सामना करना पड़ा। जब विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप की आवश्यकता थी, तो आरबीआई ने कार्रवाई की - लेकिन इसने किसी ऐसी व्यवस्था को नहीं अपनाया जिसका बचाव करना मुश्किल हो। भारत का चालू खाता घाटा प्रबंधनीय था और विदेशी मुद्रा का जोखिम बना हुआ था। सबक यह है कि भारत के विकास के चरण में एक देश के लिए, पूंजी खाता उदारीकरण का अनुक्रमण कोई तकनीकी नहीं है - यह व्यापक आर्थिक संप्रभुता का पहला प्रश्न है।

यदि एशियाई संकट ने बाहरी अनुशासन के महत्व को प्रदर्शित किया, तो 2007-08 के सबप्राइम संकट ने आंतरिक अनुशासन बनाए रखने के महत्व को दर्शाया। वैश्विक वित्तीय प्रणाली 2000 के दशक के मध्य में अधिक विस्तृत और जटिल वित्तीय संरचना विकसित कर रही थी, आरबीआई कुछ ऐसा कर रहा था जो प्रचलित मानकों के आधार पर अलोकप्रिय लग रहा था। जब 2002 में, ब्याज दरें गिर रही थीं और बैंकों के पास वापसी की उम्मीद करने का कोई कारण नहीं था, तो आरबीआई ने उनसे ठीक उसी स्थिति के बदले निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व नामक एक काउंटर-साइक्लिकल बफर बनाने की मांग की। बाद में, वर्ष 2005-07 के दौरान, अन्य बातों के साथ-साथ वाणिज्यिक स्थावर संपदा के लिए जोखिम भारिता और प्रावधान संबंधी अपेक्षाएं बढ़ाई गई थीं। प्रतिभूतिकरण हेतु लाभ की मान्यता को प्रतिभूतियों की अवधि पर विस्तारित करना आवश्यक था। इसके अलावा, उस समय के लेखांकन मानकों ने अप्राप्त लाभ की मान्यता की अनुमति नहीं दी थी।

इनमें से कोई भी उस समय विशेष रूप से लोकप्रिय नहीं था। लेकिन जब वैश्विक वित्तीय प्रणाली दबाव में आ गई, तो इन उपायों को महत्व मिला। भारतीय बैंक अपेक्षाकृत सुदृढ़ तुलन पत्र के कारण संकट से बाहर आए।

हम वित्तीय स्थिरता को महत्व देना जारी रखते हैं। पिछले दशक में कई उपाय किए गए हैं। 2015 में शुरू की गई आस्ति गुणवत्ता समीक्षा, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016; वैश्विक मानकों के अनुरूप विवेकपूर्ण मानदंडों का संरेखण और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अभिशासन सुधार उनमें से कुछ हैं।

इनके कारण, हमारी वित्तीय प्रणाली आज बहुत मजबूत और आघात-सहनीय है, जिससे आर्थिक विकास का समर्थन होता है।

III. विकासात्मक भूमिका

मूल्य और वित्तीय स्थिरता बनाए रखना अधिकांश केंद्रीय बैंकों के मुख्य दायित्व हैं लेकिन आरबीआई की भूमिका इन सीमाओं से परे है। हमारी विकासात्मक भूमिका बड़ी है।

आरबीआई ने वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने जन धन कार्यक्रम के लिए सरकार के साथ सहयोग किया, जिसे 2014 में मिशन मोड पर लॉन्च किया गया था। इस मिशन के तहत आधार नामक डिजिटल पहचान और मोबाइल पहुँच का लाभ उठाते हुए, भारत ने पिछले दशक में मानव इतिहास में सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन अभियान चलाया। 570 मिलियन से अधिक बैंक खाते उन लोगों के लिए खोले गए जिनके पास कभी एक भी नहीं था। आज लगभग हर किसी के पास बैंक खाता है। इसने सरकारों से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को सक्षम बनाया, जिसने बिचौलियों को दरकिनार कर दिया। इसने लीकेज को खत्म कर दिया। इस क्रांति ने लोगों को चुपचाप सशक्त बनाया।

RBI ने UPI के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह बिना किसी समानता के एक सफलता की कहानी है। आज, दुनिया के वास्तविक समय के डिजिटल भुगतान की मात्रा में भारत की हिस्सेदारी लगभग आधी है। यूपीआई ने इस साल मार्च में 22 अरब से अधिक लेनदेन किए। आरबीआई के विकासात्मक जनादेश, एक मजबूत डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, व्यापक मोबाइल स्वामित्व और कम लागत वाली डेटा पहुँच के साथ-साथ बैंकिंग क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी उपस्थिति ने

भारत को डिजिटल भुगतान में छलांग लगाने में मदद की। हम पहले ही यूपीआई को 8 देशों में स्वीकृति के साथ वैश्विक स्तर पर ले चुके हैं और अब इसे यूरोपीय सेंट्रल बैंक के टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम (टिप्स) सहित कई और देशों से जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं।

हम वर्तमान में उधारदाताओं को डेटा तक तत्काल डिजिटल पहुँच प्रदान करने के लिए यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई) का निर्माण कर रहे हैं, जिससे उन्हें छोटे किसानों और व्यवसाय मालिकों के लिए मिनटों के भीतर क्रेडिट योग्यता का आकलन करने की अनुमति मिलती है जिनके पास पहले दिखाने के लिए कोई दस्तावेज नहीं थे या उन्हें बैंक में काफी समय और प्रयास खर्च करना पड़ता था।

हम अपने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) के साथ सीमाओं को भी आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें सीमा पार भुगतान को तेज और सस्ता करने की क्षमता है। हम विशिष्ट उपयोगों और उद्देश्यों के लिए भुगतान को निर्देशित करने के लिए प्रोग्रामेबिलिटी का भी परीक्षण कर रहे हैं।

हमारा विकासात्मक जनादेश समावेशी विकास के राष्ट्रीय लक्ष्य में मदद करता है।

V. निष्कर्ष

अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

भारतीय अर्थव्यवस्था का लचीलापन संयोग से नहीं है। यह मजबूत नीतिगत ढांचे के कारण है जिसे सफलतापूर्वक विकसित किया गया है। यह मजबूत और विश्वसनीय संस्थानों के कारण है जिन्हें परिश्रमपूर्वक बनाया गया है। यह पिछले कुछ वर्षों में लगातार किए गए विभिन्न सुधारों के कारण है। यह स्थिरता और समावेशन की नींव पर टिका हुआ है।

इन शब्दों के साथ, मैं आप सभी को आपके धैर्यवान दर्शकों के लिए धन्यवाद देता हूँ। मुझे प्रश्नों का उत्तर देने में खुशी होगी, यदि कोई हो।